Hkkjrh; turk ikVh }kjk i:dkf'kr] 11] v'kksd jkM] ubZ fnYyh & 110 001

भाजपा का आरोप पत्र

कांग्रेस नेतृत्व

की संप्रग सरकार के दस वर्षों का काला युग

संक्षिप्त विवरण

विषय सूची

परिचय

1.0 प्रधानमंत्री पद की गरिमा और समग्रता के साथ समझौता

2.0 भारत की अर्थव्यवस्था का विनाश

3.0 घोटालों और भ्रष्टाचार की एक अंतहीन गाथा

4.0 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ

5.0 विदेश नीति की विफलता

6.0 पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा

7.0 शिक्षा एवं स्वास्थ्य

8.0 सस्थानों की महत्ता को कम करना

9.0 कांग्रेस घोषणा पत्र 2009 में उल्लेखित वादों में विफल रहने पर आरोप (कांग्रेस घोषणापत्र के क्रमानुसार सूचीबद्ध)

10.0 निष्कर्ष

कांग्रेस नेतृत्व की संप्रग सरकार के दस वर्षों का कालायुग
भाजपा का आरोप पत्र
संक्षिप्त विवरण

परिचय

राजग ने अपने शासन काल में एक खुशहाल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। इस दौरान 6 करोड़ 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए एवं महंगाई की दर को 5% तक नियंत्रित करके रखा गया था। अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से प्रगति कर रही थी, इसका उल्लेख 2003–04 के आर्थिक सर्वे में श्री पी.चिदम्बरम के द्वारा भी किया गया था। 10 वर्ष के शासन के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व ठहराव की ओर धकेल दिया जहाँ अर्थव्यवस्था 4.6% के दयनीय स्तर तक जा पहुँची। यूपीए की सरकार ने राजग शासन के दौरान हासिल की गई आर्थिक ताकत को मजबूत करने का अवसर गँवा दिया।

इसके अतिरिक्त यूपीए सरकार अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देने में नाकाम रही। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और शासन में जड़ता की वजह से इस सरकार ने निवेशकों, युवाओं और नागरिकों का विश्वास खो दिया। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में गृह मंत्रालय की विफलता विशेष रूप से दिल्ली में नियमित तौर पर सामने आई।

भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े कारनामों के बीच शासन करने की प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति का सर्वथा अभाव दिखा। यूपीए 2 सरकार निर्णय लेने में अपंग सिद्ध हुई, जिसकी वजह से नीतियों में ठहराव आ गया। केबिनेट ने वस्तुतः काम किया ही नहीं इसका स्थान GOMS, EGOMS और संविधानेतर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के हस्तक्षेप ने ले लिया। Business World ने 16 दिसम्बर 2013 को अपनी एक रिपोर्ट में इसे “Panel Overload” की संज्ञा देते हुए लिखा है सामूहिक निर्णय और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कुल 30 Groups of Ministers और Empowered groups of Ministers का गठन किया गया। लेकिन इनके प्रभावी होने के विषय में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। कुछ मंत्री तो 27 से लेकर 6 Groups of Ministers के सदस्य थे”।

Pew Research Group की एक रिपोर्ट (Feb 26, 2014) के अनुसार ”जिस प्रकार से देश में चीजें घटित हो रही हैं उसके कारण प्रत्येक 10 में से 7 भारतीय नाखुश हैं“ http://www-pewglobal-org/2014/02/26/indians-want-political-change/

2014 के चुनावों की घोषणा के समय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था, ”मैंने कम बात की है। मेरे लिए मेरा काम बोलेगा“। लेकिन उनका काम चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने, भ्रष्टाचार पर आँखें मूंदने, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन, विदेश नीति एवं रक्षा नीति में विफलता और महत्वपूर्ण संस्थाओं की महत्ता घटाने के तौर पर सामने आये हैं, जैसा कि हमारे आरोप पत्र में उल्लेखित है।

इस संक्षिप्त आरोप पत्र में विभिन्न मदों के तहत हमारे आरोप हैं, जिसका विस्तार सम्बंधित बिंदु में दिया गया है। सभी आरोप सहायक तथ्यों और उनके स्रोतों के साथ हैं, जिन्हें मुख्य दस्तावेज में अनुबंध के रूप में विस्तार के साथ दिया गया है।

1. प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा और समग्रता के साथ समझौता

भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। प्रधानमंत्री केवल सरकार का ही मुखिया नहीं होता है बल्कि उसे देश का भी नेता होना चाहिए। आखिरी फैसला लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले बोर्ड के CEO के बतौर कार्य किया, जहाँ राहुल गांधी उनके डिप्टी थे।

डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए हर प्रकार का समझौता किया। प्रधानमंत्री ने किसी भी अवसर पर लगातार हो रहे घोटालों और जनता के पैसे की लूट को रोकने में सक्रियता नहीं दिखाई। इन्हीं कारणों की वजह से इस सरकार को आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार कहा गया है। घोटालों के कई प्रकरणों में स्वयं प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका संदेह के गंभीर दायरे में है। प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को नष्ट करने में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी बराबर के भागीदार हैं। वे बिना किसी उत्तरदायित्व के सत्ता की असीमित शक्तियां अपने पास रखना चाहते थे। कई अवसरों पर घटित भारी गलतियाँ और अनियमितताएं इन दोनों के स्वीकृति और अनुमोदन से हुई हैं।

यूपीए के शासन में प्रधानमंत्री पद का अवमूल्यन हुआ, इसकी गरिमा के साथ समझौता किया गया एवं लचर शासन

प्रणाली का खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा। असुरक्षा की भावना से देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर आघात लगा।

2. भारत की अर्थव्यवस्था का विनाश

राजग सरकार ने 1998 में सत्ता संभाली, तब भारत की विकास दर 4.8ः प्रतिशत थी. जब मई 2004 में राजग सरकार सत्ता से हटी तब यह विकास दर 8.5% के मजबूत आंकड़े को छू चुकी थी। राजग सरकार ने यह उपलब्धि पोखरण 2 के बाद लगे वैश्विक प्रतिबंधों, कारगिल युद्ध, संसद पर हुए हमले, गुजरात में आए भूकंप, 2002 के सूखा और तमाम अन्य बाधाओं के बावजूद हासिल की थी। श्री पी. चिदम्बरम को भी 2005 के आर्थिक सर्वे में इस तथ्य का उल्लेख करना पड़ा कि वर्ष 2003–04 में देश की अर्थव्यवस्था श्रेष्ठतम स्तर 8.5% पर थी, जो कि पिछले 30 वर्षों के दौरान 2 अवसरों को छोड़कर उच्चतम स्तर था।

राजग ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति दर्ज की एवं यूपीए के हाथों में एक बेहतर अर्थव्यवस्था सुपुर्द की, लेकिन यूपीए ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक इंजन को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट है।

क्रमांक	सूचक	1997–98	2003–04	2012–13	2013–14
1	सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर	4.3%	8.5%	4.96%	4.6% (till Dec- 2013)
2	औद्योगिक वृद्धि – दर	4.01%	7.32%	2.1%	–2% (निर्माण)
3	सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का %	5.66%	4.34%	5.2% (5.7% पद 2011–12)	
4	बचत दर – सकल घरेलू उत्पाद का %	24.1%	32.41% से 2004–05	30.2%	
5	चालू खाता घाटा – सकल घरेलू उत्पाद का %	–2%	–2.7% (अधिशेष)	–4.8% (घाटा)	
6	विदेशी कर्ज (अरब डॉलर में)		$112-7 billion	$ 390 billion	
7	लघु अवधि का बाहरी कर्ज– सकल घरेलू उत्पाद का %		3.9%	24.8%	

2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.2% के राजकोषीय घाटे को योजना व्यय में 90000 करोड़ रुपये की कटौती के द्वारा प्राप्त किया जा सका। 2013–14 में भी 4.6% के राजकोषीय घाटे को योजना व्यय में 79790 करोड़ रुपये की कटौती करके पूरा किया गया।

(Source: Budget speech, Planning Commission databook for Deputy Chairman dated 18/12/2013, Economic Survey 2004-05, CSO data and RBI's Handbook of Statistics on Indian Economy for 2012-13)

रुपये की कीमत में गिरावट

चालू खाता अधिशेष का घाटे में बदल जाना रूपये की कीमत में गिरावट का कारण बना है। रुपये की कीमत में गिरावट से आयात महंगा हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल हैं, जो कि पूर्ण रूपेण विदेशों से आयात किये जाते हैं। इसकी वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी।

पिछले वर्षों में रूपये की कीमत डॉलर में				
	1998–99	2003–04	29th August, 2013	March, 2014
एक डॉलर की कीमत (रूपये में)	42	45.9	67.7	61

(Source: RBI Handbook of Statistics)

महंगाई को नियंत्रित करने में विफलता

राजग सरकार के सत्ता से हटने के समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.86% था। राजग सरकार के बेहतर आर्थिकी प्रबंधन की बदौलत कीमतें नियंत्रण में थीं। यूपीए सरकार में महंगाई की दर निम्नानुसार रही।

Year	UPA	Year	UPA	Year	UPA
2004-2005	3-9	2005-2006	4-2	2007-2008	6-8
2008-2009	9-1	2009-2010	13-0	2010-2011	9-5
2011-2012	9-0	2012-2013	8-0	Average	7-93

(Source: Planning Commission Databook for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec- 2013)

इस प्रकार यूपीए के शासन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करीब 8% (7.93%) रहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने सार्वजनिक तौर पर यह वादा किया था कि अगले 100 दिनों के अन्दर महंगाई कम हो जायेगी, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया और जनता महंगाई से तडपती रही। वास्तव में इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का इरादा गंभीर संदेह पैदा करने वाला रहा है। यह सरकार अपने निहित स्वार्थों के चलते कभी भी महंगाई को कम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखी। इसके अतरिक्त खाद्य अर्थव्यवस्था में सकल कुप्रंधन भी इसका कारण रहा है।

बढ़ती बेरोजगारी–यूपीए सरकार की भारी विफलता

कुप्रबंधन की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए, इसलिए रोजगार के अवसरों में भी भारी गिरावट आई। यूपीए सरकार का रोजगार सृजन करने का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 1999–2000 एवं 2004–05 (राजग सरकार के 6 वर्ष) के दौरान 6 करोड़, 70 लाख रोजगार सृजित हुए, जबकि 2004–05 एवं 2011–12 (यूपीए सरकार के 8 वर्ष) के मध्य केवल 1 करोड़ 54 लाख रोजगार ही सृजित हो सके। राजग सरकार के दौरान निर्माण और सेवा क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित हुए जबकि यूपीए सरकार के दौरान स्थितियां ठीक उसके उलट हो गईं।

NSSO का 61st, 66th और 68th दौर का सर्वे हमारे दावे का समर्थन करता है।

	1999-2000 to 2004-05	2004-05 to 2011-12
रोजगार की संख्या (लाखों में)	60.7 (6.07 Cr)	15.44 (1-54 Cr)
औसत वार्षिक रोजगार सृजन (लाखों में)	12.1 (1-21 Cr)	2.2 (22 लाख)
रोजगार में कुल वृद्धि (लाखों में)	1999-2000 to 2004-05	
निर्माण	117.2	निर्माण
सेवा	187.7	सेवा

राजग सरकार में वार्षिक रोजगार सृजन 1.21 करोड़ से अधिक था जबकि यूपीए के दौरान यह घटकर महज 22 लाख प्रति वर्ष रह गया। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों को नष्ट करके यूपीए सरकार ने रोजगार के अवसरों को नष्ट कर दिया। देश का नौजवान अपने भविष्य को लेकर गंभीर अनिश्चतता के दौर से गुजर रहा है।

आधारभूत संरचना का विनाशः

अच्छा आधारभूत ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। सड़कें, बिजली, लोहा एवं स्टील उद्योग, खनन उद्योग जिसमें कोयला सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तथा बंदरगाह जहाँ से विदेशों के लिए व्यापार संचालित किया जाता है। यह सब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत ढांचे के मुख्य स्तम्भ हैं। वर्षों तक आधारभूत संरचना, लचर नीतियां, योजनाओं की मंजूरी में भ्रष्टाचार, घोटाले, विलम्ब से स्वीकृति, पर्यावरण मंत्रालय से मिलने वाली आवश्यक मंजूरी में देरी की वजह से हमारा बुनियादी ढांचा अपांग हो गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग

भूतल परिवहन मंत्रालय से प्राप्त ये आंकड़े अपनी दुखद कहानी खुद बयाँ करते हैं।

वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग लम्बाई (कि.मी.)	अतिरिक्त कि.मी	अवधि वर्ष	अतिरिक्त वार्षिक
1951 22193			
1997 34298	12105	46 years	263
2004 65569	31271	7 years	4,467
2012 76818	11249	8 years	1,406

46 वर्ष के शासन काल में कांग्रेस ने 12105 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जबकि 1997 से 2004 के अपने शासन काल के दौरान राजग ने 31271 किलोमीटर राजमार्गों क निर्माण किया। राजग सरकार ने प्रतिवर्ष 4467 किलोमीटर की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया वही UPA के 2004 से 2012 के शासन में प्रतिवर्ष 1406 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण ही हो सका।

(Source: Basic Road Statistics from Ministry of Road Transport and Highways website http://www-morth-nic-in/showfile-asp\lid (839 and http://www-morth-nic-in/showfile-asp\lid) 417)

भ्रष्टाचार, अनिर्णय, नीतियों में अपंगता की वजह से समूची आधारभूत संरचना पटरी से उतर गई। 5 दिसंबर 2013 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देते हुए राज्य सभा में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने स्वीकार किया कि *''चूँकि 2012–13 में 19 परियोजनाओं पर काम करने के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, जबकि इन परियोजनाओं के टेंडर 1 से लेकर 5 बार तक जारी किये गए थे। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 123 किमी की केवल 1 बीओटी (टोल) परियोजना, पीपीपी प्रक्रिया के तहत दे सकी। यह हमारे सड़क निर्माण गतिविधियों की सफलता में बाधक है।''*

बिजली:

(i) राष्ट्र के विकास में विद्युत् उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लगभग 68% बिजली उत्पादन ताप आधारित है। राजग सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 के माध्यम से बिजली उत्पादन लाइसेंस मुक्त किया। हालांकि, कोयला घोटाला से विद्युत उत्पादन को गंभीर झटका लगा सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान के अलावा अनियमित आपूर्ति के कारण विद्युत उत्पादन का प्रदर्शन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त KPMG की नवम्बर 2013 में जारी हुई "recharging the Power Sector" रिपोर्ट के अनुसार कोयला और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की कमी के कारण बिजली संयंत्रों की 33000 मेगावाट के आसपास की क्षमता अधर में लटक गई जिसकी वजह से इन बिजली संयत्रों में निवेश किये गए 1,00,000 करोड़ रूपये अलाभकारी साबित हो गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 के अंत तक 78 बिजली परियोजनाएं जिनसे 103000 MW बिजली का उत्पादन होना था, पर्यावरण से जुडी मंजूरी न मिलने कारण लंबित पड़ी हुई थी।

UPA II ने भारत की विद्युत स्व–पर्याप्तता को आगे बढाने के लिए कुछ नहीं किया। 11 वीं पञ्च–वर्षीय योजना के अंत में भारत को विद्युत क्षेत्र में 13% के अत्याधिक घाटा हुआ है। बिजली संयंत्रों के क्षमता के उपयोग का अनुमान प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) से पता चलता है। यह मानक भी राजग सरकार को UPA से बेहतर साबित करता है।

बिजली संयत्रों का प्लांट लोड फैक्टर			
	1998–99	2004–05	2012–13
प्लांट लोड फैक्टर	64.6%	74.8%	69.9%

(Source: Central Electricity Authority's yearly reports at website www-cea-nic-in/reports/yearly_report-html)

घोटालों और पर्यावरण मंत्रालय के कठोर कानूनों की वजह से खनन क्षेत्र में अव्यवस्था

कोयला, बाक्साइट (अल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है) और स्टील ये तीन संसाधन हर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं. आंकड़े दिखाते हैं कि यूपीए ने बुनियादी ढांचे के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किस प्रकार से गड़बड़ की है.

(i) कोयला

- भारत के पास आगामी 200 साल के लिए पर्याप्त 286 अरब टन का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है। वर्ष 2003–04 में कोयले की मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर मात्र 23.57 लाख टन का था। वर्ष 2012–13 में भारत का कोयला उत्पादन 557 लाख टन था और इस अवधि में भारत ने 140 लाख टन मंगहा कोयला आयात किया।

(Source: Economic Survey - 2012-13; Coal Ministry Website and Coal Ministry's Annual Report for 2004-05)

(ii) बॉक्साइट (अलुमिनियम के उत्पादन में प्रयुक्त)

भारत 3.5 अरब टन के भंडार के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है। हमारा उत्पादन वास्तव में 2006–07 के 22.6 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2011–12 में 12.8 करोड़ टन तक गिर गया है। (Source: Indian Bureau of Mines)

(iii) स्टील :

स्टील उत्पादन किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्ष 2012 में चीन के 716 लाख टन स्टील उत्पादन की तुलना में भारत का स्टील उत्पादन केवल 73.4 लाख टन था। भारत दुनिया का सातवाँ लौह अयस्क से समृद्ध और भंडार क्षमता वाला देश हैं, जहाँ 28.5 बिलियन टन लौह अयस्क के सुरक्षित भंडार हैं। बजाय इसके कि हम अपने पास मौजूद लौह अयस्क के भंडार से स्टील का अधिकतम उत्पादन करें, हमें भारी तादाद में स्टील का आयात करना पड़ रहा है।

- भारत ने वर्ष 2012–13 में 18.37 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया।
- हमारे पास इस्पात का सरप्लस उत्पादन हुआ करता था, लेकिन आज हम स्टील के आयात और लौह अयस्क के निर्यात पर निर्भर हो गए हैं। यह औपनिवेशिक कालखंड के उन दिनों का स्मरण है जब हम कच्चा माल बेचकर तैयार उत्पाद आयात करते थे।

स्टील आयातधनिर्यात (आंकड़े लाख टन में)

	2003–04	2011–12		2003–04	2011–12		2003–04	2011–12
आयात	1.75	6.83	निर्यात	5.21	4.04	अधिशेष/घाटा	+3.45	–2.79

(Source: Annual Report of Steel Ministry for 2004-05 and 2012-13)

(iv) बंदरगाह

भारत के कुल निर्यात का 90% बंदरगाहों के माध्यम से होता है। पोर्ट उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जहाजों के लिए औसत वापसी समय है जिसमें यह देखा जाता है कि मूल रूप से एक जहाज को लोड या अनलोड होने में कितना समय लगता है और वह जल में परिचालन के लिए कितने समय में स्वतंत्र हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि इससे आयात और निर्यात की लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

भारतीय बंदरगाहों पर औसत वापसी समय (दिनों में)

Year	1996-97	2004-05	2011-12
Turnaround time in days	7-8	3-4	5-05

(Source : Economic Survey for1997-98, 2005-06 and 2012-13)

यूपीए सरकार एनडीए द्वारा हासिल दक्षता में बढ़त बनाए रखने में विफल रही।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू एवं विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में यूपीए सरकार की विफलता

- 11 वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कुल 500 बिलियन डॉलर की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। लक्ष्य तय किया गया था कि 100 अरब डॉलर निजी एवं विदेशी क्षेत्र से जुटाए जायेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से केवल 20 अरब डॉलर ही निवेश हो सका। विदेशी संस्थागत निवेशकों को 31 मार्च 2013 तक कॉरपोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए 25 अरब डॉलर तक निवेश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उन्होंने केवल 3.75 अरब डॉलर ही निवेश किया जो कि तय लक्ष्य का मात्र 15% था।
- **घरेलू संसाधनों को आकर्षित करने में भी असमर्थताः**

  11 वीं योजना के दौरान बुनियादी ढांचे में भारत का निवेश चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 20% की तुलना में मात्र 8% था, जो काफी कम है। यह अंतर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि यह सेक्टर पूंजी को आकर्षित करने में असफल रहा।
- बुनियादी सुविधाओं संपत्ति के लिए लंबी अवधि के वित्तपोषण में राष्ट्रीय बचत चौनल के लिए सरकार एक तंत्र विकसित करने में भी असफल रही। 2011–12 में घरेलू बचत की दर GDP का कुल 23 से 24 प्रतिशत तक थी,

जबकि लम्बी अवधि की बचत Instruments (life insurance funds and provident & pension funds) GDP का कुल 4.5% थी।

गरीबी :

गरीबी की समस्या का समाधान करने में विफलता

जून 2009 में संसद में राष्ट्रपति के संबोधन के माध्यम से UPA&II ने वादा किया था कि गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान विकेंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम अर्थात ग्राम सभाओं के माध्यम से की जायेगी और यह सरकार के प्रथम 100 दिवस की समय अवधि के दौरान किया जाएगा। लेकिन इस दिशा में कुछ भी कार्य नहीं किया गया। सरकार यह भी तय नहीं कर सकी कि देश में सही मायनों में गरीब है कौन? तेंदुलकर कमेटी, सेन गुप्ता कमेटी, सक्सेना कमेटी और भी विभिन्न कमेटियां और आयोग बने, लेकिन समस्या जस की तस रही। कई राज्य सरकारों ने गरीबी का निर्धारण के करने वाले मानकों पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कोर्ट में शर्मनाक हलफनामा दायर करके कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति ही गरीब की परिभाषा और गरीबी के दायरे के तहत आता है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो सार्वजनिक तौर पर घोषित कर दिया कि 12 रूपये में भरपेट खाना मिलता है। आवश्यक वस्तुओं की बेतहाशा कीमतों ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। यूपीए सरकार ने देश के गरीबों को साथ सबसे अधिक धोखा दिया है।

3. UPA सरकार के मुख्य घोटाले

2G Spectrum Scam	1,76,000 Crores	Coal Scam	1,86,000 Crores
CWG Scam	70,000 Crores	Air India Scam	64,000 Crores
Rotten Food Scam	58,000 Crores	Hasan Ali - Money Laundering Scam	54,000 Crores
K- G- Basin Scam	30,000 Crores	ISRO&Devas Scam	2,00,000 Crores
Defense Land Scam	10,000 Crores	LIC Housing Loan Scam	10,000 Crores

Source: Different media reports- Figures approximate

जनता को घोटालों की संख्या और उजागर घोटालों में लूट की राशि जानकर आश्चर्य होगा। इन तमाम घोटालों को अंजाम देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी स्वयं को गरीबों की हितैषी और विकास परक बताती है। ऊपर सूचीबद्ध प्रमुख घोटालों के अलावा यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2004 से लेकर आज तक के कुछ अन्य कुख्यात घोटालों की सूची यहाँ दी जा रही है। विवरण मुख्य आरोप पत्र में है। यह सूची सम्पूर्ण नहीं है।

अ) नोट के बदले वोट काण्ड

आ) आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला

इ) स्विस बैंक एवं अन्य माध्यमों से काला धन घोटाला

ई) अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर रिश्वत काण्ड

उ) रेलवे रिश्वत काण्ड (त्पसहंजम)

ऊ) टेट्रा ट्रक घोटाला

ए) पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजना घोटाला

ऐ) रोबर्ट वाड्रा भूमि घोटाला

ओ) बढ़ती कीमतें–महंगाई घोटाला

औ) के.जी. बेसिन तेल घोटाला

क) ऋण माफी योजना में व्यापक धांधली

4. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ

ब्राह्य सुरक्षा

आरोप :

- मात्र पिछले दो वर्षों में ही, चीनी सैनिकों द्वारा सीमा उल्लंघन की 500 से अधिक घटनाएँ हुई हैं। UPA सरकार सही ढंग से इन घटनाओं के सैन्य प्रभाव का आंकलन तथा भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने में बुरी तरह विफल रही है।
- सरकार भारत तिब्बत सीमा के हमारे पक्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास के काम में तेजी लाने में असफल रही है। वर्ष 2022 तक पूरी होने वाली सीमा सड़क की 503 परियोजनाओं में से केवल 17 अब तक पूरी हुई हैं और वर्तमान में काम सिर्फ 50 परियोजनाओं पर चल रहा है। 29 जून 2006 को सीसीएस ने 2012 तक भारत तिब्बत सीमा पर 73 सीमा सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिया था। 3,505

किमी की कुल लंबाई वाली इन सड़कों में से 15 मार्च 2013 तक केवल 527 किमी या निर्धारित सड़कों का करीब 31% ही पूरा किया जा सका।

- पाकिस्तान से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर खतरा बना हुआ है और जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ एवं संवेदनशील सुरक्षा स्थानों पर आत्मघाती हमलों के जरिये आतंकवादी भारत के खिलाफ लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पाक सीमा पर भारतीय जवानों के सिर काटे जाने की घटना से पूरे देश को आक्रोशित कर दिया था। कमजोर नेतृत्व के कारण हम पाकिस्तान को अपेक्षित जवाब नहीं दे सके। रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी ने कह दिया कि आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन कर हमला किया था. उनके इस बयान से पूरे देश में बवाल मच गया, मजबूरन उन्हें अपने बयान को वापस लेना पड़ा।

आंतरिक सुरक्षा :

आरोप :

- आंतरिक सुरक्षा का माहौल दिनोंदिन बद से बदतर होता जा रहा है। शहरों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में अपराध का बढ़ता ग्राफ लोगों के बीच जबरदस्त असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है।
- पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन में हुई धीमी प्रगति से भारत में पुलिस की कठिनाइयां बढ़ गई हैं।
- 72 लाख से अधिक आपराधिक मामले देश भर की अदालतों में लंबित हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर लोगों का विश्वास अपराधियों के मनोबल को कुचलने का कार्य करता है। सरकार को न्यायपालिका के साथ अधिक सक्रिय रूप से संवाद स्थापित करते हुए विशेष रूप से जघन्य अपराधों के कृत्यों में न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत से उन्हें अवगत कराना चाहिए था, तथा साथ ही बेहतर तरीके से त्वरित न्याय प्रदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए उन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस करना चाहिए था।
- सरकार भारत में हो रहे अवैध आप्रवासियों के घुसपैठ की रोकथाम करने में बुरी तरह विफल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारत के खिलाफ एक युद्ध के रूप में घोषित कर रखा है। बांग्लादेश से अवैध आव्रजन एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चिंता का विषय है इसके माध्यम से आतंकवादी समूहों को उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आसान जमीन मिल रही है।
- वहीं जम्मू और कश्मीर में 2008–10 के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं 150 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जबकि कई हजार अन्य घायल हो गए। करीब 3,000 पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी भी इन घटनाओं में घायल हुए। इन घटनाओं से जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विभेद की खाई भी चौड़ी हो गई।
- सरकार सुरक्षा बलों की छवि को धूमिल करने के राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रयासों पर रोक लगाने में विफल रही।
- सरकार ने अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान यात्रा करने और उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने की इजाजत देकर सीमा पार भारत विरोधी ताकतों को हमारे देश में उनके नापाक इरादों को अंजाम देने का काम किया है।
- अक्तूबर 2004 में प्रधानमंत्री ने देश के लिए सबसे बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में वामपंथी उग्रवाद को चिन्हित व सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। लेकिन इस बेहद गंभीर मसले पर सरकार की प्रतिक्रिया खतरे की गंभीरता और परिमाण के अनुरूप नहीं है। वामपंथी उग्रवाद ने पिछले एक दशक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर में हुई नागरिकों और सुरक्षा बलों की कुल मौतों से अधिक लोगों की जान ली है।
- 2005 के बाद से 6,000 से अधिक नागरिक और सुरक्षा बल कर्मी वामपंथी उग्रवाद के हमलों में मारे जा चुके हैं। भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में लगभग 170 जिले वामपंथी उग्रवाद से कुछ हद तक प्रभावित हैं। 33 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में चरमपंथियों ने कुछ ऐसे प्रक्षेत्र बना लिए हैं, जहाँ वे समानांतर सरकार चलाते हैं। भारत सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो माओवादी हिंसा के खिलाफ प्रभावित राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक प्रभावी एंव व्यापक रणनीति बनाये। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के पास इस चुनौती का मुकाबला करने और इससे निपटने के लिए किसी भी ठोस नीति का सर्वथा अभाव है। यह भी विडम्बना है कि श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कई सदस्य सार्वजनिक तौर पर माओवादियों से सहानुभूति रखते हैं, उनके पक्षधर माने जाते हैं।
- **जेहादी आतंकवाद का मुकाबला करने में विफलता:** 2005 के बाद जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर के बाहर कम

से कम 25 बड़े आतंकी हमलों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए और 3,000 से अधिक घायल हुए। इन हमलों के पीछे या तो सीधे लश्कर–ए–तैयबा या इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का हाथ था अथवा यह इन दोनों आतंकी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप इन घटनाओं को अंजाम दिया गया।

- सरकार संगठित होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र एनसीटीसी के रूप में एक केंद्रीकृत संस्था की स्थापना के लिए देश में राजनीतिक आम सहमति कायम करने में असमर्थ रही है। आतंकवादी संगठनों के बारे में खुफिया सूचनाओं की साझेदारी और एक केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई NATGRID परियोजना में भी अभी तक कुछ अधिक प्रगति देखने को नहीं मिली है।
- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। केंद्र सरकार ने पहले आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) को समाप्त कर दिया जो कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत सर्वसमान कानून था। उसी तरह इसने गुजरात के आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (GUJCOCA) को मंजूरी देने से इनकार कर दिया जबकि एक पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मकोका में इसी तरह के प्रावधान हैं। संप्रग सरकार ने बार–बार आतंकवाद के संरक्षकों को संकेत दिया कि उनके खिलाफ की गई कोई भी प्रभावी कार्रवाई उसके अपने वोट बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
- सरकार ने खुफिया एजेंसियों में संख्याबल की कमी को रेखांकित करने और उनकी तकनीकी क्षमता के उन्नयन की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। इसने विभिन्न एजेंसियों को एक–दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उनके कर्मियों का मनोबल गिराया है और राज्य संस्थाओं को भीषण रूप से कमजोर किया है। उदाहरण के तौर पर एक कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ के मामले में आईबी के अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया।
- कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को श्आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर बर्बर पुलिस कार्रवाई के शिकार के रूप में चित्रित कर के पूरी बहस का सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश कर रही है। हालांकि निर्दोष व्यक्तियों की गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है, फिर भी आतंकवाद के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई को जानबूझ कर मुसलमानों के खिलाफ लक्षित प्रताड़ना के रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति के पीछे बेहद खतरनाक और सांप्रदायिक मकसद छुपे हैं। दूसरी ओर, कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में आईएम की पहचान करने से साफ इंकार करते हैं।
- कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की संकीर्ण सांप्रदायिक मानसिकता एक बार फिर उजागर हुई जब राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक भाषण में दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर प्रदेश में दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर जिले के मुस्लिम युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने के लिए उनके साथ संपर्क में थी।
- वोटबैंक की राजनीति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। सरकार के मंत्रियों द्वारा भगवा आतंक जैसे शब्दों के प्रचलन और इसको बढ़ावा देने से आतंकियों और उनके आकाओं के हौसले बुलंद हुए हैं। बिहार सरकार की सुरक्षा लापरवाही के चलते पिछले वर्ष अक्टूबर में श्री नरेन्द्र मोदी की पटना में आयोजित हुंकार रैली में बम विस्फोट हुए, इस जेहादी घटना में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोग घायल हुए। यह एक शर्मनाक उदाहरण है कि किस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वोट बैंक आड़े आ जाता है।

5. विदेश नीति की विफलता

आरोप :

- पड़ोसी देशों के साथ भारत के राजनैतिक रसूख में गिरावट आई है। बीते 5 वर्षों के दौरान हमारी विदेश नीति में न तो आत्मविश्वास देखने को मिला और न ही सुरक्षा मुद्दों के दृष्टिगत रखते हुए अपने पड़ोसी देशों को चीन की गोद में बैठने से रोक सके। प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ हमारी साख धूमिल हुई है।
- डॉ. मनमोहन सिंह ने अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश की प्रशंसा से अपना कार्यकाल शुरू किया। वह ऐसे समय में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं जब अमरीका में भारत को अपमानित करने की तमाम घटनाएँ घट रही हैं।
- अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कजाखस्तान के साथ नागरिक परमाणु समझौतों के बावजूद भी सरकार परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली के उत्पादन के लिए रिएक्टरों को परिचालित करने में नाकाम रही है। परमाणु समझौते को यूपीए प्रथम सरकार ने भारी सफलता के तौर पर प्रचारित किया था, आज जबकि यूपीए का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है परमाणु समझौते के माध्यम से बिजली उत्पादन का कहीं भी वजूद नहीं है।

- भारत की विदेश नीति की वर्तमान दिशा से हम पूर्वी एशियाई देशों विशेष रूप से जापान और वियतनाम के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, जिससे चीन का प्रभाव कम किया जा सकता था। भारत दक्षिण चीन समुद्र चीन से धमकी के बाद तेल अन्वेषणों के कार्य से भे पीछे हट गया।

6. पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में अनदेखी

- डॉ. मनमोहन सिंह वर्ष 1991 से संसद में असम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 5 वर्ष तक भारत के वित्त मंत्री रहे और पिछले 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। बावजूद इसके असम में पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ।
- 3000 मेगावाट की दिबांग जल विद्युत् परियोजना, ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग योजना और बोघिभिली राष्ट्रीय रेल योजना लगभग बंद पड़ी हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को गति प्रदान करने के लिए राजग सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य विकास विभाग का प्रथक गठन किया था, लेकिन यूपीए सरकार में इस विभाग का काम काज ठप्प पड़ गया। राजग सरकार द्वारा आरम्भ की गई 'ईस्ट–वेस्ट' परियोजना भी संभवतः राजनैतिक पक्षपात की वजह से सुस्त पढ़ गई है।
- बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ लगातार जारी है। श्री राजीव गांधी द्वारा किये गए असम समझौते के उद्देश्य भी अधूरे पड़े हैं, जबकि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
- एक सींग वाला गैंडा प्रजाति का जीव असम राज्य के लिए एक अनूठा प्रतीक है। केवल एक ही वर्ष के अंतराल में, 258 से अधिक गैंडों का अवैध शिकार कर के मार दिया गया। केंद्र स्थित राज्य और पर्यावरण मंत्रालय इस शांत प्राणी की रक्षा में विफल रहा जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी प्राकृतिक वास के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

7. शिक्षा एवं स्वास्थ्य

IIT संस्थानों में 40% प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय संस्थानों में यह प्रतिशत 30% एवं IIM में 25% है.।

- डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से 150 तक पहुँच गई है, यह विश्वविद्यालय नियमों और मानकों के उल्लंघन करके स्थापित हो रहे हैं।

स्वास्थ्य

यूपीए 2 सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवायें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 17 फरवरी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरक पर पिछले 10 सालों में दी जाने वाली सब्सिडी पांच गुना बढ़ गई, 2004–05 में जहाँ सब्सिडी पर 5 लाख करोड़ रूपये खर्च हो रहे थे, वहीं वर्तमान वित्त वर्ष में यह खर्च बढ़कर 16.6 लाख करोड़ हो गया है। इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिए जाने वाले बजट में 20.6 % की कटौती की है।

8. संस्थानों को कमजोर करना

- कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने महत्वपूर्ण संस्थानों की पवित्रता और अखंडता को व्यवस्थित तरीके से कमजोर है उसके साथ समझौता किया है।
- कांग्रेस सरकार द्वारा सी.ए.जी. पर लगातार हमला बोला गया, क्योंकि सी.ए.जी. ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कांग्रेस के 2G, Coalgate, CWG, ISRO & Devas Antrix Deal जैसे घोटालों को उजागर किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के रूप में पी.जे. थॉमस की संदिग्ध नियुक्ति को खारिज किया।
- कांग्रेस ने अपने लोगों के भ्रष्टाचार को दबाने एवं राजनैतिक विरोधियों को फंसाने के लिए सीबीआई का दुरूपयोग किया
- महत्वपूर्ण संसदीय संस्थाओं जैसे संयुक्त संसदीय समिति और लोक लेखा समिति की गरिमा के साथ समझौता किया।
- सरकार के मंत्री चुनाव आयोग की सार्वजनिक आलोचना करते रहे।

9. कांग्रेस घोषणा पत्र 2009 में किये गए वादों को पूरा न कर पाने में विफलता को लेकर आरोप
कुछ महत्वपूर्ण वादे

वादाः 'आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस,' 'मुंबई हमलों के दोषियों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई'.

आरोप :

- वर्ष 2009 से दिसम्बर 2013 तक भारत के ऊपर 21 कम और उच्च क्षमता वाले आतंकी हमले हुए। इन हमलों में सौ से अधिक लोगों की जाने गईं और हजारों लोग घायल हुए। आतंकी हमलों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आई है।
- शीर्ष स्तर पर पाकिस्तान के साथ भारत ने 26/11 के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की पूर्व शर्त नहीं रखी। जबकि जनवरी 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मध्य हुए समझौते में कहा गया था कि पाकिस्तान उसकी भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। डॉ. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से 26/11 के हमले के बाद 8 बार मुलाकात की. पाकिस्तान की भूमि से भारत के खिलाफ आतंक को रोकने में पाकिस्तान को राजी कर पाने सरकार विफल रही।
- पाकिस्तान की जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों जमात उद दवा और लश्कर–ए–तैयबा के आतंकी कैम्पों और वहां की पंजाब सरकार द्वारा इनको आर्थिक मदद देने के विषय में भारत के पास अहम् सबूत मौजूद थे, लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा सके।
- 26/11 का मुख्य आरोपी हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा।
- जेल में बंद लश्कर के अन्य आतंकी जकी उर रहमान, रहमान लखवी, युसूफ मुज्जमिल की आवभगत की जाती रही, जो कि जेल से ही अपनी गतिविधियाँ चला रहे थे।
- सीमा पर भारतीय जवानों की हत्या और उनके सर काट लेने जैसी घटनाओं के बाद भी मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जनवरी एवं अगस्त 2013 में संयुक्त राष्ट्र सभा बैठक की पृष्ठभूमि में न्यूयॉर्क में भेंट की।

वादा : राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर 2011 के के प्रकाशन के बाद प्रत्येक भारतीय को आधार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

आरोप :

- संसद के किसी भी अधिनियम द्वारा इस महंगी और संवेदनशील कवायद का समर्थन नहीं किया गया है। UIDAI के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत कुल Rs 12,398 करोड़ के बजट में 31 जुलाई 2013 Rs 3,062 करोड़ खर्च किये गए थे। योजना आयोग राज्य मंत्री ने राज्य सभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नागरिकों की निजता का हनन रोकने की दिशा में संगृहीत डाटा साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार पहचान पत्र होना अनिवार्य नहीं है। प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह पहचान पत्र वास्तविक नागरिक के जो नागरिक अधिकार हैं उसके ऊपर है?

वादा : उच्च स्तर की रक्षा तैयारियां

आरोप :

- रक्षा खरीद में नियमित देरी, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की वजह से देश की रक्षा तैयारियों को झटका लगा है। यह समस्या रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने वाली फर्मों को बड़े पैमाने पर ब्लैक लिस्ट करने के कारण पैदा हुई, इन कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने से भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है बल्कि देरी की वजह से रक्षा खरीद में भारी इजाफा हुआ है।
- अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद के मामले में दर्ज इटली की चार्जशीट में इस कम्पनी और Finnmecanica के सी.ई.ओ. पर रिश्वत और कमीशन देने के आरोप हैं।
- सेना प्रमुख द्वारा 12.3.2012 को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि आर्मी के सभी टैंक बेड़े दुश्मन के टैंक को हराने के लिए "महत्वपूर्ण गोला बारूद से रहित है"।

- पनडुब्बियों और नौसेना के डाकयार्ड में लगातार हो रही दुर्घटनाओं से देश हैरान है। नौसेना प्रमुख ने नौसेना के सम्मान की खातिर इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन सरकार और उसके मंत्री ने इन घटनाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। नौसेना की दुर्गति करवाने के बाद भी रक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहे।
- भारत अभी भी अपनी रक्षा उपकरणों के 70% आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर है जिसके कारण कीमतों में वृद्धि की मार झेलनी पड़ती है और युद्ध के निर्णायक समय पर आपूर्तिकर्ता देश द्वारा स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में कटौती कर देने जैसे खतरे की सम्भावना भी बनी रहती है। सरकार ने हल्के लड़ाकू विमान (तेजस), मुख्य युद्धक टैंक (अर्जुन) परियोजनाओं को फिर से बहाल करने के लिए सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई है, जबकि इसके लिए कई दशक पहले खाका तैयार किया गया था।
- सरकार और सशस्त्र बलों के बीच अविश्वास का जो माहौल वर्तमान में निर्मित हो गया है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं देखा गया। इस सबका का प्रतिकूल असर हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल पर पड़ सकता है, जो कि रक्षा तैयारियों में एक बड़ा झटका साबित होगा।

वादा : "हम ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे," एवं "हम एक ऐसी योजना लेकर आयेंगे जिससे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर बिजली मिल सके"।

आरोप :

- वादाखिलाफी करके कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। ये सरकार जनता को सस्ती दरों पर बिजली दे पाने में असफल रही। मई 2004 जब NDA सरकार बाहर हुई थी तब Rs 244 की दर से पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध थे। UPA सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के दाम तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ गए आज गैस सिलेंडर की कीमत Rs 845/- है। दरअसल UPA सरकार ने सिलेंडर की संख्या को वार्षिक आधार पर सीमित करके इसे गरीब और जरूरतमंद की पहुंच से दूर बनाया है।
- कोल ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार, परियोजनाओं की मंजूरी में अनियमितता और कम उत्पादन के चलते विद्युत् क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है जबकि परमाणु उर्जा के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं।

वादा : "हम किसानों तथा उनके परिवारों की भलाई की लिए विभिन्न योजनाओं को विस्तार देंगे"

आरोप :

- दुर्भाग्यवश किसान लगातार आत्महत्या करते रहे विशेषकर कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में। किसानों की आत्महत्या के 46 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश से सामने आये हैं।
- सरकार की नीतियों के विरोध में आँध्रप्रदेश के किसानों ने फसल उत्पादन से खुद को दूर कर लिया, यह मुद्दा भाजपा द्वारा संसद में भी उठाया गया था।
- महंगाई, विकास दर में कमी और कृषि से जुड़े आवश्यक तत्वों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण में किसान त्रस्त हैं।
- यूपीए सरकार ने इस विषयक स्वामीनाथन कमेटी का भी गठन किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया।

वादा : "हम कम राजकोषीय घाटे और कम मुद्रास्फीति के माध्यम से उच्च विकास दर को बनाये रखेंगे।"

आरोप :

राजग सरकार ने 8.5% विकास दर के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था यूपीए सरकार को सौंपी थी, लेकिन यूपीए ने कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, कुशासन से आर्थिक विकास के सभी कारकों को नष्ट कर दिया और विकास दर को दयनीय 4.6% के आंकड़े तक पहुंचा दिया।

10. निष्कर्ष :

- कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार असल में इस देश के लिए भारी विपत्ति साबित हुई है। यह भारत के लोगों के लिए केवल दुख, दर्द, और निराशा की विरासत छोड़ कर जा रही है। इस दस्तावेज में यूपीए सरकार के काले कारनामों का जिक्र है जिसने देश की नींव को हिलाकर रख दिया है। ये आरोप पत्र उसी निराशा का सार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि इस सरकार और इसके पापों से मुक्त होने का समय आ गया है।

Hkkt ik dUæh; puko lfefr di fun”k ei dkxil di urRo okyh lçx ljdkj di nl o”kki di di’kklu ij vkjki i= cukui di fy, ,d mi lfefr cukbi xbA

lfefr di lnL;%

Jh xkihukFk eMi
miurk çfri{k ykd lHkk] Hkkt ik

Jh jfo’kdj çlkn
miurk çfri{k jkT; lHkk] Hkkt ik

Jherh vkjrh egjk
jk”Vh; lfpo] Hkkt ik

Jherh fueyk lhrkje.k
jk”Vh; çoDrk] Hkkt ik

Jh dhjhV lkeS;k
jk”Vh; dk;Zdkfj.kh lnL;] Hkkt ik

Jherh ehuk{kh ys[kh
jk”Vh; çoDrk] Hkkt ik

lk’ky ehfM;k] ekckbly VDukykth vkfn ek/;ek ls turk di fopkj tkuu di fy, dkmM lkfl.x fuEukfdr

श्री माधव गर्ग
श्री नीरज शर्मा
श्री राजनील कामत
श्री विकास पाण्डे
श्री विनायक डालमिया
श्री नवरंग (भाजपा आई.टी. प्रकोष्ठ)